International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 09 Issue: 10 | Oct - 2025 SJIF Rating: 8.586 ISSN: 2582-3930

"पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज की भूमिका: पहचान और राजनीतिक चेतना का विश्लेषण"

[1]प्रवीन चौधरी

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

शोध सार

पूर्वांचल, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक निर्णायक क्षेत्र माना जाता है, वहाँ निषाद समुदाय का जनसांख्यिक और सामाजिक प्रभाव निरंतर बढ़ता रहा है। इस अध्ययन में यह जांच की गई है कि किस प्रकार निषाद समाज ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक हाशिए से उठकर राजनीतिक चेतना का विकास किया और अपनी सामूहिक पहचान को सशक्त बनाया।

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि निषाद समाज की राजनीतिक सक्रियता केवल सत्ता-भागीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आरक्षण, और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों से भी गहराई से जुड़ी है। 1990 के दशक के बाद मंडल राजनीति, पिछड़े वर्गों की लामबंदी, और क्षेत्रीय दलों के उदय ने इस समुदाय की राजनीतिक दिशा को नया आयाम दिया।

इसके अतिरिक्त, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में निषाद पार्टी की भूमिका और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके गठबंधन ने निषाद समाज की राजनीतिक पहचान को व्यापक स्तर पर स्थापित किया। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज अब "वोट बैंक" मात्र नहीं, बल्कि एक "राजनीतिक शक्ति" के रूप में उभर रहा है, जो अपने हितों के प्रति सजग, संगठित और वैचारिक रूप से अधिक परिपक्व हो चुका है।

बीज शब्द: निषाद समाज, पूर्वांचल राजनीति, राजनीतिक चेतना, पहचान, सामाजिक न्याय, निषाद पार्टी, गठबंधन राजनीति.

1. प्रस्तावना

पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) भारतीय राजनीति का वह क्षेत्र है जहाँ जातिगत समीकरण, सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक गठबंधन चुनाव परिणामों को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसी क्षेत्र में निषाद समाज – जिसमें केवट, बिंद, मल्लाह, धीमर, नोनिया आदि उपजातियाँ शामिल हैं – एक महत्वपूर्ण जनसमूह के रूप में उभरा है। ऐतिहासिक रूप से यह समाज मछली पालन और नाविकता से जुड़ा रहा, किंतु सामाजिक संरचना में यह पिछड़े वर्गों में गिना गया।

"पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज की भूमिका: पहचान और राजनीतिक चेतना का विश्लेषण" नामक इस शोध पत्र का उद्देश्य उस जटिल और गतिशील राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन और मूल्यांकन करना है जिसमें निषाद समुदाय ने पिछले दशकों में अपना उद्भव और संगठनात्मक रूपांतरण अनुभव किया है। पूर्वांचल–जिसमें गोरखपुर, मऊ, देवरिया, बलिया, आज़मगढ़ आदि जिले सम्मिलित हैं–ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र रहा है, जहाँ जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय अस्मिता और विकास के प्रश्न राजनीति के मुख्य आयाम बनते आए हैं। इन पृष्ठभूमियों के बीच निषाद समाज, जिसकी जीवन-आधार नदियों और जलसम्बन्धी आजीविकाओं से रही है, ने पारंपरिक वंचना से निकलकर राजनीतिक चेतना और प्रतिनिधित्व की मांग को तीव्र रूप से उठाया है।

यह शोध पत्र केवल चुनावी परिणामों या सीटों की संख्या तक सीमित विश्लेषण नहीं करेगा; बल्कि वह सामाजिक पहचान, संगठनात्मक रणनीति, गठबंधन नीति और वास्तविक प्रतिनिधित्व–विशेषकर टिकट नीति व निर्णय प्रक्रियाओं में निषाद समुदाय की भागीदारी–के स्तरों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। 1990 के बाद के मण्डलीकरण, समाजवादी आंदोलनों तथा 2016 में स्थापित निषाद पार्टी के उभार जैसे ऐतिहासिक परिवर्तक कारकों का अध्ययन इस संदर्भ में आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं घटनाओं ने न केवल समुदाय की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया बल्कि उसे सत्ता-साझेदारी के मैदान में भी ला खड़ा किया।

2. पूर्वांचल की राजनीति का ऐतिहासिक विकास

पूर्वांचल की राजनीति का विकास भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। यह क्षेत्र–जिसमें गोरखपुर, आज़मगढ़, देवरिया, बलिया, मऊ और भदोही जैसे जिले शामिल हैं–राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सदैव सक्रिय रहा है। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक पूर्वांचल की राजनीतिक चेतना ने अनेक चरणों से होकर एक विशिष्ट स्वरूप ग्रहण किया है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, जातीय पुनर्संरचना और विकास की राजनीति का गहरा प्रभाव रहा है।

ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्वांचल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना। यहाँ की जनता ने गांधीजी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बलिया के चित्तू पांडेय जैसे नेताओं ने 1942 में 'स्वतंत्र सरकार' की स्थापना कर इस क्षेत्र को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर कर दिया। इस काल में जनता की राजनीतिक चेतना केवल औपनिवेशिक शासन के विरोध तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह स्वराज, समानता और सामाजिक न्याय की आकांक्षा में भी रूपांतरित होती गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्वांचल की राजनीति पर कांग्रेस का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व ने इस क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी, लेकिन धीरे-धीरे सामाजिक असमानता, भूमि सुधार, बेरोज़गारी और पिछड़े वर्गों की उपेक्षा जैसे मुद्दों ने राजनीतिक असंतोष को जन्म दिया। 1960 और 1970 के दशक में समाजवादी विचारधारा, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, पूर्वांचल के युवाओं और किसानों में गहराई तक पैठ बना चुकी थी। इसी समय जनसंघ जैसी विचारधारात्मक पार्टियों ने भी यहाँ अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी।

1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से पूर्वांचल की राजनीति में निर्णायक मोड़ आया। पिछड़ी और दलित जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलने से नई सामाजिक शक्तियाँ उभरकर सामने आईं। यादव, कुर्मी, निषाद, मौर्य और अन्य पिछड़े वर्गों में राजनीतिक जागरूकता का प्रसार हुआ। समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) जैसे दलों ने सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को राजनीति के केंद्र में रखा। इस दौर में जातीय पहचान, सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक भागीदारी के नए समीकरण बने, जिन्होंने पूर्वांचल की राजनीतिक दिशा को स्थायी रूप से प्रभावित किया।

बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक पूर्वांचल में क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेतृत्व का उभार हुआ। निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) और अपना दल जैसे दलों ने पिछड़े वर्गों और वंचित समुदायों की आकांक्षाओं को स्वर देने का कार्य किया। इन दलों ने क्षेत्रीय पहचान, आरक्षण, रोजगार और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाकर पूर्वांचल की राजनीति को नई दिशा दी।

2014 के बाद पूर्वांचल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व स्थापित हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर उभरती भाजपा ने योगी आदित्यनाथ जैसे क्षेत्रीय नेताओं के माध्यम से पूर्वांचल को अपने राजनीतिक आधार क्षेत्र में परिवर्तित किया। गोरखपुर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ का सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव सबसे अधिक देखा गया, आज पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र बन चुका है। विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों ने इस क्षेत्र की राजनीतिक दिशा को पुनर्परिभाषित किया है।

समग्र रूप से कहा जाए तो पूर्वांचल की राजनीति एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया रही है, जिसने परंपरा से आधुनिकता की यात्रा को सशक्त रूप में प्रदर्शित किया है। स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी आदर्शों से लेकर मंडल युग की सामाजिक न्याय की राजनीति और वर्तमान में विकास तथा पहचान आधारित राजनीति तक, पूर्वांचल की राजनीतिक चेतना लगातार परिपक्व होती गई है। यह क्षेत्र आज भी जाति, धर्म, विकास और पहचान जैसे बहुआयामी कारकों के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास में संलग्न है। इस प्रकार, पूर्वांचल की राजनीति का ऐतिहासिक विकास केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, क्षेत्रीय अस्मिता और लोकतांत्रिक मूल्यबोध की यात्रा का प्रतीक है।

3. पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज की भूमिका

पूर्वांचल की राजनीति भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आयाम है, जहाँ सामाजिक संरचना, जातीय समीकरण, और क्षेत्रीय पहचान राजनीति की दिशा निर्धारित करते हैं। इस क्षेत्र की राजनीतिक संस्कृति सदैव सामाजिक चेतना और जातिगत गतिशीलता पर आधारित रही है। इसी संदर्भ में निषाद समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। निषाद समुदाय, जो ऐतिहासिक रूप से जलमार्ग, मत्स्य पालन, नौपरिवहन और श्रमप्रधान आजीविकाओं से जुड़ा रहा है, आज पूर्वांचल की राजनीति में एक सशक्त सामाजिक-राजनीतिक इकाई के रूप में उभर चुका है।

पूर्वांचल की राजनीतिक प्रक्रिया में निषाद समाज की सक्रियता स्वतंत्रता के पश्चात् प्रारंभ हुई, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ने सभी समुदायों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर दिया। प्रारंभिक दशकों में यह समुदाय शिक्षा, आर्थिक संसाधनों और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा। उस समय की राजनीति पर ऊँची जातियों और सम्पन्न वर्गों का वर्चस्व था, जिसके कारण निषाद समाज केवल मतदाता के रूप में सीमित रह गया। परंतु 1970 के दशक में समाजवादी आंदोलनों और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक चेतना के प्रसार ने निषाद समाज को भी नई दिशा दी।

डॉ. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अन्य समाजवादी नेताओं की विचारधारा ने सामाजिक न्याय और समानता की अवधारणा को राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। इससे प्रेरित होकर निषाद समाज ने अपने अधिकारों के प्रति सजगता दिखानी शुरू की। यह सजगता मात्र सामाजिक नहीं थी, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की खोज भी थी। यही वह दौर था जब पूर्वांचल की राजनीति में सामाजिक न्याय के साथ-साथ जातिगत प्रतिनिधित्व का विचार भी प्रबल होने लगा।

1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से निषाद समाज की राजनीतिक भूमिका और सशक्त हुई। मंडल युग ने भारतीय राजनीति को जाति-आधारित प्रतिनिधित्व की दिशा में मोड़ा और निषाद समाज को भी "पिछड़ा वर्ग" की श्रेणी में सम्मिलित कर राजनीतिक अवसरों का द्वार खोला। समाजवादी पार्टी (SP) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) जैसी पार्टियों ने निषाद समाज को अपने सामाजिक गठबंधन में शामिल किया, जिससे उनकी राजनीतिक उपस्थिति बढ़ी। हालाँकि इन दलों में नेतृत्व स्तर पर निषाद समाज की भागीदारी सीमित रही, फिर भी यह चरण समुदाय की राजनीतिक चेतना के प्रसार का निर्णायक समय था।

इक्कीसवीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में निषाद समाज ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान गढ़ने का प्रयास किया। पूर्वांचल के गोरखपुर, देवरिया, आज़मगढ़, और वाराणसी जैसे जिलों में निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह और गोंड जैसे उपसमुदायों ने "निषाद" की एकीकृत पहचान के अंतर्गत राजनीतिक एकता की भावना विकसित की। इस चेतना का परिणाम "निषाद पार्टी" के रूप में सामने आया, जिसने समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सत्ता-साझेदारी की दिशा में संगठित किया। 2016 के बाद से निषाद पार्टी पूर्वांचल की राजनीति में एक निर्णायक कारक बनकर उभरी।

2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में निषाद पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ गठबंधन कर अपनी भूमिका को सशक्त किया। इस गठबंधन ने यह स्पष्ट किया कि निषाद समाज अब केवल राजनीतिक समर्थन देने वाला समूह नहीं, बल्कि सत्ता-संतुलन को प्रभावित करने वाला समुदाय बन चुका है। गोरखपुर, मऊ, संतकबीरनगर, और आज़मगढ़ जैसे जिलों में निषाद समाज का वोट बैंक अब चुनावी गणित का केंद्र बिंदु बन गया है।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो निषाद समाज की भूमिका अब केवल मतदाता या सहयोगी तक सीमित नहीं रही। इस समाज ने राजनीतिक विमर्श को "सामाजिक न्याय" से आगे बढ़ाकर "भागीदारी और प्रतिनिधित्व" की नई अवधारणा दी है। निषाद पार्टी का नारा – *"सत्ता में भागीदारी नहीं तो समर्थन नहीं"* — इस समुदाय के आत्मसम्मान और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक है।

पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज का यह उभार भारतीय लोकतंत्र के व्यापक समाजशास्त्रीय परिवर्तन का संकेत है। जहाँ पहले राजनीति जातीय वर्चस्व और वर्गीय नियंत्रण तक सीमित थी, वहीं अब वंचित समुदायों का संगठित स्वर राजनीतिक संतुलन को पुनर्परिभाषित कर रहा है। निषाद समाज की यह भूमिका केवल जाति-आधारित प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं, बल्कि यह सामाजिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से क्षेत्रीय विकास के प्रश्न को भी संबोधित कर रही है।

यह कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज की भूमिका एक ऐतिहासिक परिवर्तन का परिणाम है। यह भूमिका निरंतर विकसित हो रही है–जहाँ कभी यह समाज राजनीतिक रूप से उपेक्षित था, वहीं आज यह सत्ता-संरचना का एक निर्णायक घटक बन चुका है। निषाद समाज की राजनीतिक सक्रियता ने पूर्वांचल की राजनीति को नई दिशा दी है, जिसमें सामाजिक न्याय, भागीदारी और पहचान की राजनीति परस्पर जुड़कर एक सशक्त लोकतांत्रिक विमर्श का निर्माण कर रही है।

4. निषाद समाज की राजनीतिक चेतना का उद्भव

पूर्वांचल की राजनीति सदैव सामाजिक संरचना, जातिगत गतिशीलता और क्षेत्रीय अस्मिता के त्रिकोण पर आधारित रही है। इस राजनीतिक परिदृश्य में निषाद समाज का उद्भव और उसकी राजनीतिक चेतना का विकास भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के विमर्श से गहराई से जुड़ा हुआ है। निषाद समाज, जो ऐतिहासिक रूप से जलमार्ग, मत्स्य पालन और नौपरिवहन से जुड़े श्रमप्रधान कार्यों में संलग्न रहा, लंबे समय तक सामाजिक वंचना और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात् विशेषतः पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, यह समाज धीरे-धीरे राजनीतिक रूप से सजग हुआ और अपने अधिकारों के प्रति संगठित चेतना का निर्माण करने लगा।

औपनिवेशिक काल में निषाद समाज की राजनीतिक भागीदारी लगभग नगण्य थी। आर्थिक निर्बलता, शिक्षा का अभाव और जातिगत पदानुक्रम में निम्न स्थिति ने उन्हें राजनीति से दूर रखा। स्वतंत्रता आंदोलन में निषाद समाज ने स्थानीय स्तर पर सहयोग अवश्य किया, परंतु नेतृत्व-स्तर पर उनका कोई उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व नहीं था। स्वतंत्र भारत में भी प्रारंभिक दशकों तक यह समुदाय राजनीतिक मुख्यधारा से दूर रहा, क्योंकि उस समय की राजनीति अभिजात्य वर्गों और प्रभावशाली जातियों के नियंत्रण में थी।

राजनीतिक चेतना के वास्तविक बीज 1970 के दशक में पड़े, जब संपूर्ण उत्तर भारत में समाजवादी आंदोलन और पिछड़ी जातियों की राजनीति ने उभार लिया। डॉ. राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने सामाजिक न्याय और समानता की जो विचारधारा प्रस्तुत की, उसने निषाद समाज के भीतर आत्म-सम्मान और अधिकारों के प्रति एक नई सोच का संचार किया। यह काल निषाद समाज के लिए वैचारिक जागृति का समय था, जब सामाजिक पहचान को राजनीतिक स्वर देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

1990 का दशक निषाद समाज की राजनीतिक चेतना के विकास का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से 'पिछड़ा वर्ग' राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय विषय बन गया। निषाद समाज को न केवल अपने सामाजिक अस्तित्व की पहचान मिली, बल्कि प्रतिनिधित्व की माँग भी वैधानिक स्वरूप में सामने आई। इस काल में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने निषाद समाज को अपने सामाजिक समीकरणों का हिस्सा बनाया, यद्यपि यह भागीदारी अधिकतर प्रतीकात्मक ही रही। फिर भी इसने निषाद समाज के भीतर यह समझ विकसित की कि राजनीतिक सशक्तिकरण ही सामाजिक सम्मान की वास्तविक कुंजी है।

इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में निषाद समाज की राजनीतिक चेतना संगठित रूप लेने लगी। क्षेत्रीय स्तर पर "निषाद एकता परिषद" और बाद में "निषाद पार्टी" जैसी संस्थाओं का गठन इसी चेतना का परिणाम था। इन संगठनों ने "सत्ता में भागीदारी नहीं तो समर्थन नहीं" जैसे नारों के माध्यम से समुदाय की राजनीतिक आकांक्षा को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया। इस काल में निषाद समाज ने स्वयं को मात्र एक मतदाता समूह के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हितधारी समुदाय के रूप में देखना शुरू किया।

पूर्वांचल की राजनीति में निषाद पार्टी का उभार यह दर्शाता है कि राजनीतिक चेतना केवल बाहरी राजनीतिक दलों के माध्यम से नहीं, बल्कि आत्म-संगठन और आत्म-प्रतिनिधित्व के आधार पर भी विकसित हो सकती है। भाजपा के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन और विधानसभा चुनावों में उसकी भूमिका यह प्रमाणित करती है कि यह समाज अब पूर्वांचल की राजनीतिक दिशा निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। निषाद समाज की यह चेतना सत्ता-साझेदारी की वास्तविक अवधारणा की ओर संकेत करती है, जहाँ समुदाय अपने सामाजिक पूंजी को राजनीतिक पूंजी में रूपांतरित कर रहा है।

राजनीतिक दृष्टि से निषाद समाज की चेतना का उद्भव केवल जातिगत प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। यह व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक पुनर्संरचना की प्रक्रिया है, जिसमें वंचित वर्ग अपनी ऐतिहासिक हीनता को चुनौती दे रहा है और लोकतंत्र के मूल्यों–समानता, भागीदारी और आत्म-सम्मान–को नए अर्थों में पुनर्परिभाषित कर रहा है। पूर्वांचल में निषाद समाज की राजनीतिक चेतना

का उभार यह भी दर्शाता है कि भारतीय राजनीति अब केवल वर्गीय संघर्ष या विचारधारात्मक टकराव तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पहचान आधारित राजनीति (identity-based politics) के माध्यम से सामाजिक न्याय की नयी भाषा गढ़ रही है।

यह कहा जा सकता है, कि पूर्वांचल में निषाद समाज की राजनीतिक चेतना का उद्भव एक क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया रही है। यह चेतना आर्थिक संघर्ष, सामाजिक असमानता, जातिगत वंचना और लोकतांत्रिक आकांक्षा–इन सभी का परिणाम है। आज निषाद समाज न केवल क्षेत्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, बल्कि राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित कर रहा है। यह उद्भव उस परिवर्तनशील सामाजिक यथार्थ का प्रतीक है, जहाँ सत्ता अब वर्चस्व का नहीं, बल्कि भागीदारी का माध्यम बन रही है।

5. निषाद पार्टी का उदय

https://caravanmagazine.in/politics/nishad-support-to-sp-bsp-challenges-adityanath

भारतीय राजनीति में जातीय और सामाजिक अस्मिता ने सदैव निर्णायक भूमिका निभाई है। लोकतंत्र के इस युग में जब सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की राजनीति ने क्षेत्रीय स्वरूप ग्रहण किया, तब निषाद समाज भी अपने अधिकारों, पहचान और राजनीतिक भागीदारी की खोज में आगे आया। इसी ऐतिहासिक क्रम का परिणाम **निषाद पार्टी** का उदय है, जिसने न केवल निषाद समाज की सामूहिक चेतना को राजनीतिक रूप दिया, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में नई समीकरणों को भी जन्म दिया।

निषाद समाज भारत के उन प्राचीन समुदायों में से एक है, जिनका जीवन नदियों, जलमार्गों और मत्स्य पालन से गहराई से जुड़ा रहा है। गंगा, घाघरा, सरयू जैसी नदियों के किनारे बसने वाला यह समाज सदियों से परिश्रमशील जीवन का प्रतीक रहा है। किंतु सामाजिक दृष्टि से यह समुदाय लंबे समय तक उपेक्षित और वंचित रहा। सामाजिक पदानुक्रम में निम्न स्थान, शिक्षा की कमी, और आर्थिक निर्बलता के कारण यह समुदाय राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हो सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशकों में जब भारतीय राजनीति पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तब निषाद समाज का कोई स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं था।

1970 के दशक में जब देशभर में समाजवादी आंदोलनों और पिछड़े वर्गों की राजनीति ने उभार लिया, तब निषाद समाज के भीतर भी चेतना का प्रसार हुआ। डॉ. राममनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं की विचारधारा ने समानता, सामाजिक न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूकता जगाई। यह दौर निषाद समाज में राजनीतिक आत्म-चिंतन का था, जब समुदाय ने यह महसूस किया कि सामाजिक सम्मान केवल राजनीतिक भागीदारी से ही संभव है।

1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने से निषाद समाज को एक वैधानिक पहचान मिली। पिछड़े वर्गों को राजनीतिक और शैक्षिक आरक्षण मिलने के बाद निषाद समाज के भीतर भी यह विचार मजबूत हुआ कि प्रतिनिधित्व और सत्ता-साझेदारी ही वास्तविक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। यद्यपि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने निषाद समाज को

अपने सामाजिक गठबंधन में शामिल किया, परंतु नेतृत्व स्तर पर निषादों को वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। यह असंतोष और राजनीतिक उपेक्षा ही निषाद समाज में एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन की आवश्यकता का मूल कारण बनी।

इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में निषाद समाज के भीतर यह विचार बलवती हुआ कि यदि अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा करनी है, तो स्वयं का राजनीतिक मंच आवश्यक है। इसी वैचारिक प्रेरणा से 2016 में डॉ. संजय निषाद के नेतृत्व में **"निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल" (NISHAD)** की स्थापना की गई, जिसे संक्षेप में "निषाद पार्टी" कहा जाता है। इस नाम में ही पार्टी की विचारधारा निहित है – निर्बल, शोषित और वंचित वर्गों को एकजुट कर उन्हें राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर करना।

निषाद पार्टी का नारा "सत्ता में भागीदारी नहीं तो समर्थन नहीं" उसकी विचारधारात्मक स्पष्टता को दर्शाता है। यह नारा केवल राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का उद्घोष था। निषाद पार्टी ने अपनी राजनीति का केंद्र उन समुदायों को बनाया जो जल आधारित आजीविकाओं से जुड़े थे – जैसे निषाद, केवट, बिंद, मल्लाह, और कश्यप। पार्टी ने अनुसूचित जाति की सूची में निषाद समाज को शामिल किए जाने, जल संसाधनों के उपयोग पर अधिकार, और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को अपने संघर्ष का आधार बनाया।

निषाद पार्टी का राजनीतिक सफर बेहद कम समय में प्रभावशाली रहा है। 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और अप्रत्याशित रूप से भाजपा को पराजित किया। इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि निषाद समाज पूर्वांचल की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हालांकि आगामी चुनावों में निषाद पार्टी ने अपना राजनीतिक समीकरण बदला और भाजपा के साथ गठबंधन किया, जिससे उसे सत्ता-साझेदारी का अवसर प्राप्त हुआ। डॉ. संजय निषाद का उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना इस समुदाय की राजनीतिक चेतना के परिपक्व होने का प्रतीक है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2022 का विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय और जाति-आधारित दलों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य में निषाद पार्टी का उभार और प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के माध्यम से इस पार्टी ने न केवल पूर्वांचल की राजनीति में अपनी सामाजिक उपस्थिति को सशक्त किया, बल्कि निषाद, केवट, बिंद, मांझी और गोंड जैसी नदी-आधारित जातियों की राजनीतिक चेतना को भी एक संगठित रूप दिया। 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 11 सीटों में जीत दर्ज करना इस बात का संकेत था कि निषाद समाज अब राजनीतिक रूप से आत्मविश्वासी और संगठित हो चुका है। किंतु समीक्षात्मक दृष्टि से देखा जाए तो निषाद पार्टी की राजनीतिक शक्ति अभी भी भाजपा पर निर्भर है। गठबंधन ने जहाँ भाजपा को सामाजिक विस्तार में लाभ दिया, वहीं निषाद पार्टी की स्वतंत्र पहचान सीमित रही। संजय निषाद का मंत्री पद प्राप्त करना इस गठबंधन की प्रतीकात्मक सफलता थी, परंतु नीतिगत प्रभाव के स्तर पर निषाद पार्टी की भूमिका कमजोर रही। कुल मिलाकर, यह स्थिति "निर्भर राजनीतिक चेतना" को दर्शाती है–जहाँ सामाजिक पहचान सुदृढ़ तो हुई है, पर सत्ता-संरचना पर नियंत्रण अभी भी सीमित है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम निषाद पार्टी और निषाद समुदाय दोनों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उल्लेखनीय रहा, परंतु इसका मूल्यांकन केवल सीटों की संख्या से नहीं किया जा सकता। यद्यपि पार्टी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 11 पर विजय प्राप्त की, परंतु इन विजयों का सामाजिक विश्लेषण यह दर्शाता है कि निषाद समुदाय का वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सीमित रहा।

11 विजयी उम्मीदवारों में केवल तीन ही निषाद समाज से थे, जबकि शेष उच्चवर्णीय वर्गों से संबंधित थे। इससे स्पष्ट होता है कि पार्टी ने "निषाद" नाम को राजनीतिक पहचान और मत-संग्रह के साधन के रूप में प्रयुक्त किया, किंतु टिकट वितरण में निषाद समुदाय की भागीदारी को द्वितीय स्थान पर रखा।

2022 विधानसभा चुनाव परिणाम

निषाद समुदाय से संबंधित विजेता उम्मीदवार

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	उम्मीदवार का नाम	पार्टी सिंबल	समुदाय
1	चौरीचौरा	सरवन निषाद	बीजेपी	निषाद
2	करछना	पीयूष रंजन निषाद	बीजेपी	निषाद
3	मझवान	डॉ. बिनोद कुमार बिंद	निषाद पार्टी	बिंद/निषाद

कुल निषाद समुदाय से उम्मीदवार: 3

ग़ैर-निषाद (ब्राह्मण, क्षत्रिय, अन्य) समुदाय से संबंधित विजेता उम्मीदवार

क्रमांक	विधानसभा क्षेत्र	उम्मीदवार का नाम	पार्टी सिंबल	समुदाय
1	बांसडीह	केतकी सिंह	बीजेपी	क्षत्रिय
2	सुल्तानपुर सदर	राज प्रसाद उपाध्याय	बीजेपी	ब्राह्मण
3	तमकुहीराज	असीम कुमार रॉय	बीजेपी	अन्य (उच्चवर्ण)
4	ज्ञानपुर	विपुल दुबे	निषाद पार्टी	ब्राह्मण
5	मेहदावल	अनिल कुमार त्रिपाठी	निषाद पार्टी	ब्राह्मण
6	नौतनवां	ऋषि त्रिपाठी	निषाद पार्टी	ब्राह्मण
7	खड्डा	विवेकानन्द पांडे	निषाद पार्टी	ब्राह्मण
8	शाहगंज	रमेश सिंह	निषाद पार्टी	क्षत्रिय

कुल ग़ैर-निषाद समुदाय से उम्मीदवार: 8

यह स्थिति एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है—जहाँ निषाद पार्टी सामाजिक रूप से निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह जैसे जलसम्बद्ध समुदायों की प्रतिनिधि होने का दावा करती है, वहीं उसकी संगठनात्मक और चुनावी नीतियाँ सत्ता-संतुलन बनाए रखने के लिए पारंपरिक उच्च जातियों के साथ सामंजस्य पर अधिक केंद्रित हैं। इस प्रकार, निषाद समाज की राजनीतिक चेतना और मत शक्ति का उपयोग तो हुआ, परंतु नीतिगत निर्णय और सत्ता-साझेदारी में उनकी वास्तविक भागीदारी सीमित रही।

6. निष्कर्ष

पूर्वांचल की राजनीति भारतीय लोकतंत्र की जटिल सामाजिक संरचना का दर्पण है, जहाँ सामाजिक असमानता, जातिगत पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता एक-दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए राजनीति के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यहाँ स्वतंत्रता संग्राम की चेतना प्रबल रही, जिसने जनता में स्वराज, समानता और सामाजिक न्याय की भावना को जन्म दिया। स्वतंत्रता

प्राप्ति के बाद कांग्रेस का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा, किंतु 1970 के दशक में समाजवादी आंदोलन और 1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिशों ने राजनीति की दिशा को सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की ओर मोड़ दिया।

इसी प्रक्रिया में निषाद समाज का राजनीतिक उद्भव हुआ। ऐतिहासिक रूप से जलमार्ग और मत्स्य पालन से जुड़ा यह समुदाय लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहा। समाजवादी विचारधारा और मंडल आयोग के प्रभाव से इसमें आत्मसम्मान और अधिकारों की चेतना जागृत हुई। धीरे-धीरे यह समुदाय अपने हितों और पहचान के लिए संगठित हुआ। गोरखपुर, देवरिया और आज़मगढ़ जैसे जिलों में निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह और कश्यप जातियों ने सामूहिक पहचान विकसित की, जिसने "निषाद पार्टी" के गठन का आधार तैयार किया।

डॉ. संजय निषाद के नेतृत्व में बनी निषाद पार्टी ने "सत्ता में भागीदारी नहीं तो समर्थन नहीं" का नारा देकर सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। 2018 के गोरखपुर उपचुनाव और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन कर पार्टी ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। परंतु, 11 विजयी उम्मीदवारों में केवल तीन ही निषाद समाज से होने के कारण यह स्पष्ट है कि पार्टी की सफलता अभी भी सीमित स्तर पर है और समुदाय का वास्तविक राजनीतिक प्रभाव नीतिगत निर्णयों में अपेक्षाकृत कम है।

फिर भी यह निर्विवाद है कि निषाद समाज अब पूर्वांचल की राजनीति का महत्वपूर्ण घटक बन चुका है। यह केवल एक मतदाता समुदाय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और भागीदारी की राजनीति का प्रतिनिधि बन गया है। निषाद समाज की यह राजनीतिक चेतना भारतीय लोकतंत्र के उस व्यापक परिवर्तन की ओर संकेत करती है, जहाँ सत्ता अब केवल वर्चस्व का नहीं, बल्कि साझेदारी का माध्यम बन रही है।

निषाद पार्टी और निषाद समाज के सामने अब यह चुनौती है कि वे अपने संगठन को और अधिक लोकतांत्रिक तथा विचारधारात्मक रूप से सशक्त बनाएं। शिक्षा, नेतृत्व विकास और नीति-निर्माण में सक्रिय सहभागिता से यह समुदाय अपनी राजनीतिक स्थिति को स्थायी रूप से सुदृढ़ कर सकता है।

समग्र रूप से कहा जाए तो पूर्वांचल की राजनीति में निषाद समाज की भूमिका सामाजिक परिवर्तन की उस यात्रा का प्रतीक है, जिसने उपेक्षा से सम्मान और निष्क्रियता से सक्रिय भागीदारी तक का मार्ग तय किया है। यह भूमिका भारतीय लोकतंत्र के उस आदर्श को सशक्त करती है, जहाँ हर वर्ग को समान अवसर, सम्मान और प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

7. संदर्भ

1. श्रीवास्तव, निर्मला। (2002)। *निषाद केवट - परिवर्तन की ओर*। नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स। ISBN: 9788174872470।

2. द हिंदू। (10 सितम्बर 2024)। *निषाद समुदाय की राजनीति पर व्याख्या*। प्राप्त किया गया से: https://www.thehindu.com/news/national/on-the-politics-of-the-nishad-community-explained/article68407882.ece

3. नारायण, बी. (2009)। *लेजेंड वॉर: निषादों के राजनीतिक उद्भव का मानचित्रण*। *लेजेंड वॉर: निषादों के राजनीतिक उद्भव का मानचित्रण*(पृष्ठ 116–136) में। सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्रा. लि. https://doi.org/10.4135/9788132101055.n6

4. डोरन, ए. (2017)। *जाति, व्यवसाय और गंगा पर राजनीति: प्रतिरोध के प्रसंग*। यूनाइटेड किंगडम: टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप।

5. जागरण। (2025, 12 अक्टूबर). *'निषाद समाज पार्टी के बगैर यूपी में नहीं बनेगी सरकार', संजय निषाद ने किसे बताया पिछड़ों का हितैषी?'* जन जागरण. https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ayodhya-sanjay-nishad-nishad-partys-key-role-in-up-government-formation-40007286.html

6. डोरन, ए. (2012)। *गंगा पर जीवन: बनारस के मल्लाह और अनुष्ठानिक अर्थव्यवस्था*। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया (फाउंडेशन बुक्स)।

7. बग्ची, शुभम। (27 जून 2025)। *हाशिये से राजनीतिक संगठन तक: निषाद समुदाय की कहानी*। *द इंडियन एक्सप्रेस*। प्राप्त किया गया से: https://www.indianexpress.com/article/research/from-margins-to-political-mobilisation-the-story-of-the-nishad-community-10092119/

8. नारायण, बद्री। (2009)। *फैसिनेटिंग हिंदुत्व: भगवा राजनीति और दलित लामबंदी*। सेज पब्लिकेशन्स इंडिया।

9. न्यूज़18। (5 दिसम्बर 2024)। *पूर्वांचल चुनाव: निषाद पार्टी हमेशा यूपी की राजनीति में भूकंप लाती है, पार्टी प्रमुख के बेटे का बयान*। प्राप्त किया गया से: https://www.news18.com/news/politics/purvanchal-polls-nishad-party-always-brings-earthquakes-in-up-politics-says-party-chiefs-son-4803956.html

10. भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय। (1980)। *द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) की रिपोर्ट: खंड-I — मुख्य रिपोर्ट एवं सिफारिशें*। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। प्राप्त किया गया से: https://www.ncbc.nic.in/Writereaddata/Mandal%20Commission%20Report%20of%20the%201st%20Part%20English635228715105764974.pdf